माननीय न्यायालय जवाहर लाल गुप्ता, न्यायमूर्ति

मनमोहन मेहता और अन्य- याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, -उत्तरदाता

1983 का सी. डब्ल्यू. पी. 2798

18 दिसंबर, 1996

भारत का संविधान 1950—अनुच्छेद 14 & 16— वेतनमान की समानता- स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभागों में काम करने वालों के साथ वेतनमान में समानता से इनकार करने की चुनौती-अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करना - कर्मचारियों की दो श्रेणियों को समान रूप से नहीं रखा गया है-सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ समान वेतनमान प्रदान करना असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना होगा।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि शुरू से आज तक स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में अधीक्षकों को एक अलग श्रेणी के रूप में माना गया है और उन्हें सरकार के अन्य विभागों में अधीक्षकों की तुलना में कम वेतनमान में रखा गया है। हेड क्लर्कों के संबंध में भी स्थिति समान है। इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारी हमेशा अन्य विभागों में अधीक्षकों और प्रधान लिपिकों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों को दिए जाने वाले वेतनमान से कम वेतनमान में रहे हैं।

(पैरा 5, 6 और 7)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि कर्मचारियों की दो श्रेणियों को समान रूप से नहीं रखा गया है। सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ उन्हें आंशिक रूप से वेतनमान प्रदान करना गैर-कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करना होगा। यह अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। वर्तमान में, याचिकाकर्ताओं के दावे को अस्वीकार करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई कानूनी कारणों के साथ-साथ तथ्यों पर भी आधारित है। नतीजतन, यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करता है।

(पैरा 9)

सी. एम. चोपड़ा, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता

गुरिंदर सिंह, उत्तरदाताओं के अधिवक्ता

फैसला

जवाहर लाल गुप्ता, न्यायमूर्ति

(1) इन छह रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में अधीक्षक और प्रधान लिपिक के रूप में काम कर रहे हैं। वे वेतनमान के मामले में भेदभाव की शिकायत करते हैं। अधीक्षकों ने 1

1 अप्रैल, 1979 से उत्तरदाताओं को 1,000-1,500 रुपये के पैमाने में रखने के लिए निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने की प्रार्थना की। इसी तरह, प्रधान लिपिक प्रार्थना करते हैं कि उन्हें 700-1,250 रुपये के पैमाने में रखा जाए। पक्षकारों के विद्वान वकील ने 1983 की सिविल रिट याचिका संख्या 2798 में बताए गए तथ्यों का उल्लेख किया है।इन पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

(2) इस मामले में याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालयों में अधीक्षक के रूप में काम कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, हरियाणा राज्य में अधीक्षकों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। पहली श्रेणी में सिविल सचिवालय और वित्तीय आयुक्त के कार्यालय में काम करने वाले अधीक्षक शामिल थे। वे शुरू में 500-900 रुपये के वेतनमान में 900-1,100 रुपये के चयन ग्रेड के साथ काम कर रहे थे। उन्हें 100 रुपये के विशेष वेतन के साथ 1,000-1,500 रुपये के पैमाने पर रखा गया था। 100 रुपये के विशेष वेतन के साथ 1,600 रुपये के निश्चित वेतन के साथ एक चयन ग्रेड को भी मंजूरी दी गई थी। अधीक्षकों की सभी शेष श्रेणियों को 1,000-1,500 रुपये के पैमाने में रखा गया था। सिविल सचिवालय/वित्तीय आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधीक्षकों और अधीक्षकों की शेष तीन श्रेणियों के बीच एकमात्र अंतर यह था कि सचिवालय में काम करने वालों को विशेष वेतन और चयन ग्रेड प्रदान किया गया था, जबकि अन्य के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वे अधीक्षक के रूप में भी काम कर रहे हैं और इस तरह, उन्हें दूसरे अधीक्षकों के समान व्यवहार करने का अधिकार था। स्वास्थ्य सेवा निदेशक के साथ-साथ सरकार के सचिव द्वारा उनके दावे की विधिवत सिफारिश की गई थी। हालांकि, इस दावे को स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने वर्तमान रिट याचिकाओं के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति आर एस मोगनिया द्वारा 25 मार्च, 1994 के आदेश के माध्यम से एक निर्देश दिया गया था, जिसके द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के मामले को विसंगति समिति के समक्ष रखे ताकि यह पता लगाया जा सके कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और आयुक्त की सिफारिशों को क्यों स्वीकार नहीं किया गया और हरियाणा वेतन आयोग की सिफारिशों का जब उसने सभी श्रेणियों के अधीक्षकों के लिए समान वेतनमान की सिफारिश की थी, तो याचिकाकर्ताओं के मामले में उनका पालन क्यों नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में। यह मामला हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त और सचिव श्री जे. डी. गुप्ता, स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त और सचिव श्री रघबीर सिंह और हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के संयुक्त सचिव श्री जे. के. गुप्ता की एक समिति के समक्ष रखा गया। मामले पर विचार करने वाली समिति ने पाया कि याचिकाकर्ताओं के दावे को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकाः—

(i) अन्य विभागों की तुलना में स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति की संरचना और माध्यम में महत्वपूर्ण संरचनात्मक और पदानुक्रमित अंतर हैं।

(ii) स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का दावा केवल "नामकरण और पदनाम

की समानता" पर आधारित था।

(3) नतीजतन, इसने याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावे को खारिज कर दिया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत 31 अक्टूबर, 1994 की विसंगति समिति रिपोर्ट के निष्कर्षों की एक नक़ल मार्क 'ए' के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई है।

(4) याचिकाकर्ताओं ने समिति द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए अपनी याचिकाओं में संशोधन नहीं किया है। हालांकि, यह तर्क दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभागों में काम करने वालों के साथ वेतनमान के मामले में समानता से इनकार करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। क्या ऐसा है?

(5) यह स्वीकृत स्थिति है कि वर्ष 1964 से पहले, स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में अधीक्षकों के कोई पद नहीं थे। ये पद केवल लिपिकों और प्रधान लिपिकों के थे। वर्ष 1964 में मुख्य लिपिकों के पद 116-250 रुपये के पैमाने पर थे। कुछ मौजूदा पदों को उन्नत किया गया और 250-350 रुपये के पैमाने में रखा गया। इन अपग्रेडेड पदों को 'अधीक्षक' के रूप में नामित किया गया था। जो व्यक्ति वास्तव में प्रधान लिपिक के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें अधीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया और 250-350 रुपये के पैमाने में रखा गया। उस समय सरकार के अन्य विभागों में काम करने वाले अधीक्षक वास्तव में 350-450 रुपये के पैमाने पर थे। इस प्रकार, शुरुआत में, स्वास्थ्य विभाग में तथाकथित अधीक्षकों को सरकार के अन्य विभागों में अधीक्षकों के बराबर नहीं रखा गया था। इसके बाद 1 फरवरी1969 से वेतनमान में संशोधन किया गया। इस संशोधन के समय, सरकार के विभिन्न विभागों में अधीक्षकों को 400-650 रुपये के पैमाने पर रखा गया था। इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं जैसे अधीक्षकों को 300-550 रुपये के पैमाने में रखा गया था। इसके अलावा, 1 अप्रैल, 1979 से वेतनमान में एक और संशोधन किया गया। इस अवसर पर भी, सरकार के विभिन्न विभागों में अधीक्षकों को 1,00-1,500 रुपये के पैमाने पर रखा गया था, जबकि याचिकाकर्ताओं को 700-1,400 रुपये के वेतनमान की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रारंभ से लेकर आज तक स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में अधीक्षकों को एक अलग श्रेणी के रूप में माना गया है और उन्हें सरकार के अन्य विभागों में अधीक्षकों की तुलना में कम वेतनमान में रखा गया है।

(6) यहां तक कि प्रधान लिपिकों के संबंध में भी स्थिति समान है। स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में, प्रमुख क्लर्क शुरू में 116-250 रुपये के पैमाने पर थे, जो 1 फरवरी, 1969 से प्रभावी थे, उन्हें 160-400 रुपये के पैमाने पर रखा गया था जिसे संशोधित कर 1 अप्रैल, 1979 से 525-1,050 रुपये कर दिया गया था। इसके विपरीत, सरकार के विभिन्न अन्य विभागों में प्रधान लिपिक हमेशा स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए अनुमत पैमाने से अधिक थे। वे शुरू में 160-400 रुपये के पैमाने पर थे जिन्हें संशोधित किया गया और 1 फरवरी, 1969 से प्रभावी रूप से 225-500 रुपये कर दिया गया। इसके बाद इसे संशोधित किया गया और 1 अप्रैल, 1979 से इसे बढ़ाकर 700-1,250 रुपये कर दिया गया।

(7) उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग

के अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारी हमेशा अन्य विभागों में अधीक्षक और प्रधान लिपिक के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों को दिए जाने वाले वेतनमान की तुलना में कम वेतनमान में रहे हैं।

(8) क्या कारण थे? ये इस अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में समिति द्वारा

पारित आदेश में सामने लाए गए हैं।सबसे पहले, यह बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रधान लिपिकों को लिपिक के पदों से पदोन्नत किया गया था, जबकिअन्य विभागों में एक लिपिक को उप-विभागीय लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया था और फिर सहायक/वरिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया था।अंत में, मुख्य लिपिक के पद पर नियुक्ति सहायकों/वरिष्ठ लेखा लिपिकों में से की गई थी।इस प्रकार, एक व्यक्ति को प्रधान लिपिक के पद पर पहुंचने द्वारा पहले पोस्टिंग के तीन माध्यमों द्वारा गुजरना पड़ता था।इसके विपरीत, स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क को सीधे हेड क्लर्क के पद पर पदोन्नत किया गया।इसी तरह, अधीक्षकों के मामले में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, प्रधान लिपिकों के पदों को अधीक्षकों के पदों में उन्नत किया गया था और छह पदों के पदधारियों को अधीक्षकों के रूप में फिर से नामित किया गया था।इसके विपरीत, सरकार के अन्य विभागों में, एक व्यक्ति को क्लर्क, एक उप-मंडल क्लर्क, एक सहायक/वरिष्ठ लेखा क्लर्क, हेड क्लर्क और फिर अधीक्षक के रूप में काम करने के बाद अधीक्षक के रूप में पदोन्नति मिली।

(9) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों को समान रूप से नियुक्त नहीं किया गया है।उन्हें सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान प्रदान करना असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना होगा।यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।वर्तमान में, याचिकाकर्ताओं के दावे को अस्वीकार करने में प्रतिवादी की कार्रवाई कानून में अच्छे कारणों के साथ-साथ तथ्यों पर भी आधारित है। नतीजतन, यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करता है।

(10) किसी अन्य आधार पर जोर नहीं दिया गया है।

(11) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है। नतीजतन, इन्हें खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, इन मामलों की परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा